SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: It is a very important question put by the hon. member. I would like to assure you that Water has got five to six husbands just like *Draupadi.* We have got the Ministry of Water Resources, Ministry of Urban Development, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Agriculture and then the Ministry of Rural Development. We have got all the Ministries. It is not that we have earmarked this amount of Rs. 24,500 crores from our Ministry. I have already told, while answering the question, that we have earmarked this money not from our budget but it is a blueprint, it is a vision of the Ministry to arrest the declining ground water resources. We have to do something.

Banks in Gujarat

*286. SHRI LALIT BHAI MEHTA:††
SHRIMATI SAVITA SHARDA:

Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details regarding State Banks, Nationalised Banks, Private Banks, Foreign Banks and Urban Co-operative Banks giving their numbers and branches thereof, working in the State of Gujarat as on 31st December, 2002;

(b) the deposits and advances for the years 1998 to 2002 of these banks;

(c) the details of advances made to Government sponsored schemes by these banks from 1998 to 2002;

(d) whether it is a fact that except the Urban Co-operative Bank, other banks have failed to finance the trade, industry, self-employed sector, Government sponsored schemes in Gujarat; and

(e) the steps taken to bridge credit requirement in Gujarat?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH):(a) to (e) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Details regarding number of branches, deposits and advances of State Bank of India and its subsidiaries, nationalised banks, private sector banks, foreign banks and urban co-operative banks in the State of Gujarat is given in the enclosed Statement (*See* below).

---

††The question was actually asked on the floor of the house by Shri Lalit Bhai Mehta.

(c) Details of advances made to Government sponsored schemes by the above banks during the years 1998 to 2002 are as under:

March ended	Fresh advances made by banks (Rs. in crores)
1998	175
1999	218
2000	225
2001	249
2002	307

(d) and (e) No, Sir. The banks have been making advances to trade, industries, self-employed sector and Government sponsored schemes in the State of Gujarat. There is significant increase in credit advanced by all banks in the State, which has gone up from Rs. 21,917 crores as on March 1999 to Rs. 35,434 crores by December 2002. District Credit Plans (DCPs) are being prepared and implemented under lead bank schemes. Implementation of these DCPs is being monitored at District and State level. Achievements under these plans remain almost 100%.

Statement

Bank group-wise number of Banks, branches, deposits & advances in Gujarat

(Rs. in Crores)

Sl. No	Bank Group	No. of Banks	No. of Branches	Deposits					Advances				
		31.12.02	31.12.02	March 1998	March 1999	March 2000	March 2001	March 2002	March 1998	March 1999	March 2000	March 2001	March 2002
1.	SBI & Associates	8	837	8347	9541	11265	13056	15367	5611	6397	7565	8549	8342
2.	Nationalised Bank	19	2254	24717	29156	32768	36432	41624	9500	11182	12900	14466	16272
3.	Private Banks	26	146	1179	1835	2484	3646	4890	1295	2051	2632	3013	3001
4.	Foreign Banks	6	8	86	53	225	302	556	110	190	149	393	508
5.	Urban Co-operative	351	762	9048	13276	16703	17791	16506	6823	8446	10488	11864	11004

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह बताया है कि गुजरात में पब्लिक सैक्टर बैंक्स और स्टेट बैंक ग्रुप्स के द्वारा जो राशि ऋण के रूप में दी जाती है वह करीब 40 प्रतिशत चार साल की आती है। देश के कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ऋण दिया जाता है, उसका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो है, चंडीगढ़ में 150 परसेंट है, महाराष्ट्र में 95 परसेंट है, दिल्ली, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु सभी में 60 परसेंट, 62 परसेंट से ज्यादा है। गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, औद्योगिक प्रवृत्ति चलती है और गुजरात औद्योगिक दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात को इतना कम ऋण क्यों दिया जा रहा है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है।

श्री सभापति: क्या दूसरा प्रश्न भी साथ में ही करना है? आप दूसरा सप्लीमैंट्री क्वेश्चन भी साथ कर रहे हैं?

श्री ललितभाई मेहता: सभापति महोदय, प्रश्न का पार्ट टू भी इसमें शामिल है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मंत्री जी ने यह बताया है कि सरकारी जो योजनाएं होती हैं, इनके लिए जो ऋण दिया जा रहा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लैवल पर योजना बनती है, टारगेट्स तय किए जाते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि इन योजनाओं के तहत उपलब्धियां लगभग शत प्रतिशत हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान...

श्री सभापति: ध्यान मत आकर्षित करो, आप क्वेश्चन पूछो।

श्री ललितभाई मेहता: यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो आंकड़े हैं, वे यह बताते हैं कि यह बात सही नहीं है। महोदय, मुझे अपनी बात की पुष्टि के लिए आंकड़े देने की जरूरत पड़ेगी।

श्री सभापति: आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। आप भी होशियार हैं और फाइनेंस मिनिस्टर आपसे ज्यादा होशियार हैं।

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो क्रेडिट डिपॉज़िट अनुपात या रेशो के बारे में है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्रेडिट प्लान या उनके डिसबर्समैंट के बारे में है। जहां तक क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात या रेशो का सवाल है, डिपॉजिट अधिक और क्रेडिट कम इसलिए है क्योंकि जो व्यवसायी हैं, वे अपना व्यवसाय यदि गुजरात से बाहर करेंगे तो क्रेडिट अपने आपमें बाहर उठाया जाएगा किन्तु उसके पीछे यह कहना कि किसी प्रकार से गुजरात की उपेक्षा हो रही है, यह सही नहीं है। दूसरा सवाल डिस्ट्रिक्ट क्रैडिट प्लान के बारे में है। इसका जवाब बहुत लम्बा बन जाएगा इसलिए अगर आप इजाजत दें तो इसका जवाब मैं भिजवा दूंगा।

श्री सभापति: एक बात की जानकारी मैं प्राप्त करना चाहूंगा कि सारी स्टेट्स में क्रेडिट डिपॉज़िट रेशो में बहुत बड़ा अंतर है। सारी स्टेट्स की यह कम्पलेंट हो सकती है कि हमारे यहां

डिपॉज़िट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम मिलता है। उस संबंध में सरकार ने कोई विचार किया हो तो वह बताएं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, निश्चित रूप से इस रेशो को या इस अनुपात को बनाने के पीछे लक्ष्य यही है कि क्रेडट डिपॉज़िट रेशो मे जब अंतर होता है तो राज्य को किसी प्रकार की कठिनाई के कारण हो रहा है या अपने आपमें राज्य वहां उतना क्रेडिट नहीं उठाना चाहता। हम निरंतर इस बात की जांच करते रहते हैं और हमारा मंत्रालय इस संबंध में पूर्ण रूप से सजग है।

श्री ललितभाई मेहता: महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है।

श्री सभापति: बस हो गया। आपने दो सप्लीमेंटरी कर लिए हैं।

श्री ललितभाई मेहता: मैंने दो सप्लीमेंटरी नहीं पूछे।

श्री सभापति: माफ करना, बहुत प्रश्न बाकी रह गए हैं। इसलिए जिनके नाम लिखे हुए हैं, मैं केवल उनसे ही पूछने को कहूंगा।

श्रीमती सविता शारदा: महोदया, मेरे पास लगभग 19 बैंकों की लिस्ट है जिसमें एस.जी.एस. वाई. बैंकों के द्वारा इनडिविजुअल और ग्रुप वाइज़ जो ऐप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, उसमें मैं देखती हूं कि पैंडिंग ऐप्लीकेशंस 6,478 हैं, रिटर्निंग 17,901 हैं और रिजैक्टिड 1,847 हैं। सभापति महोदय, इतने सारे लोग ऋण मांग रहे हैं तो उनको कोई न कोई जरूरत होगी किन्तु बैंकों के द्वारा राशि उनको नहीं मिल रही है। यह तो 2002 तक के आंकड़े हैं, 2003 तक पैंडिंग ऐप्लीकेशंस और ज्यादा बढ़ गयी होंगी। इसे मंत्री महोदय कब तक पूरा करेंगे? इसके अतिरिक्त जो महिलाओं के द्वारा सैल्फ हैल्प ग्रुप्स चलाए जाते हैं, फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स और ऐग्रो प्रोसैसिंग यूनिट्स चलाए जाते हैं, इसके लिए भी क्या बैंकों में कुछ योजनाएं हैं और अगर सरकार के पास ऐसी कुछ योजनाएं हैं तो उनका क्रमबद्ध ब्यौरा क्या है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्या ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो पैंडिंग ऐप्लीकेशंस की संख्या इतनी अधिक क्यों है? उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पैंडिंग की संख्या स्थिर नहीं होती। किसी एक तारीख पर जब यह प्रश्न पूछा गया है, उससे क्या आंकड़े निकाले जाते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, उसके अनुसार इतने पैंडिंग हैं। प्रयत्न यह रहता है कि कम से कम पैंडिंग हों। यह संख्या निरंतर कम होती जाती है तथा दूसरी ऐप्लीकेशंस भी आती रहती हैं। सैल्फ हैल्प का मैं पहले ही कह चुका हूं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बहुत सफल हैं और पिछले वर्ष करीब 600 करोड़ रुपये लोन उनको दिया जा चुका है। गुजरात में सैल्फ हैल्प ग्रुप्स अभी इतने सफल नहीं हो रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इस संबंध में राज्य सरकार सजग हो तो हमारी तरफ से हम पूरी मदद करेंगे।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I would like to put a very important supplementary to this particular question.

श्री सभापति: बस, अब हो गया।

गंगा नदी का निजीकरण

*287. **श्री रमाशंकर कौशिक:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी विदेशी कंपनी के साथ गंगा नदी के निजीकरण के सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी का नाम क्या है और वह किस देश से संबंधित है तथा उक्त सौदे के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौदे से संबंधित निबंधन और शर्तें क्या हैं और उक्त सौदे के परिणामस्वरूप देश को होने वाले अनुमानित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Privatisation of River Ganga

†*287. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a deal has been signed by Government with a foreign company for the privatisation of the river Ganga;

(b) if so, the name of the company in the country in which it is based alongwith the details of the circumstances responsible for the said deal; and

(c) the terms and conditions of the deal and the details of the estimated profit/loss to the country as a result of the said deal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY): (a) So far as Central Government is concerned no such deal has been signed.

(b) and (c) Do not arise.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.